



गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बेटे, बेटि को मार कर

कारोबारी ने पत्नी व महिला सहयोगी संग की खुदकुशी

आशीष दुबे
गाजियाबाद, 3 दिसंबर।

इंदिरापुरम के वैभव खंड स्थित कृष्णा सैफायर सोसायटी की आठवीं मंजिल से कूदकर एक कारोबारी, उसकी पत्नी और कारोबार में सहयोग करने वाली एक महिला ने मंगलवार सुबह जान दे दी।

फ्लैट की बालकनी में तीन कुर्सियां लगी मिली हैं। कुर्सियों पर चढ़कर एक साथ सुबह करीब सवा पांच बजे तीनों ने आत्मघाती कदम उठाया। इससे पहले कारोबारी ने अपनी 18 वर्षीय बेटि और 15 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने बताया कि कारोबारी ने दिल्ली में रहने वाले अपने भाई हरीश वासुदेव को वीडियो कॉल के जरिए बच्चों की हत्या करने और खुद के

18 साल की बेटि और 15 साल के बेटे को मार फिर आठवीं मंजिल से कूदकर जान दी कारोबारी गुलशन ने आर्थिक तंगी के चलते उठाया आत्मघाती कदम सुसाइड नोट में साहू को दहराया जिम्मेदार साहू के साथ दो करोड़ रुपए को लेकर विवाद चल रहा था



घटनास्थल पर पुलिसकर्मी

आत्महत्या करने के फैसले की जानकारी भी दी।

पुलिस के मुताबिक कारोबारी ने बेटे की हत्या गर्दन पर चाकू से वार कर और बेटि की हत्या गला दबाकर की। कमरे की दीवार

पर लिखे सुसाइड नोट में कारोबारी ने अपने साहू राकेश वर्मा को जिम्मेदार ठहराते हुए आर्थिक तंगी की बात कही है। साथ ही पांचों शवों का अंतिम संस्कार एक साथ बाकी पेज 8 पर

पाक गोलाबारी में महिला और किशोर की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 दिसंबर।

जम्मू-कश्मीर से सटी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से बीते 24 घंटे से रुक-रुककर भारी गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तानी सेना के जवान रुक-रुककर पुंछ जिले में एलओसी से सटे तमाम हिस्सों में रिहाइशी इलाकों और सेना की पोस्टों पर गोलाबारी कर रहे हैं।

रिहाइशी इलाकों में गोलाबारी के कारण दो स्थानीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा नौ लोग घायल हुए हैं। गोलाबारी का भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तान को दोपहर करीब 2.30 बजे पुंछ से सटे दो सेक्टरों में गोलाबारी की।

पाकिस्तानी जवानों ने पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टरों में 182 एमएम के मोर्टार दागे, जिसके कारण यहां कई मकानों को भी नुकसान हुआ। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एलओसी पार से गोलाबारी जारी है।

प्रवक्ता के मुताबिक, शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी और गोलाबारी में 35 वर्षीय एक महिला गुलनाज अख्तर और 16 वर्षीय एक

किश्तवाड़ में आतंकी पकड़ा गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 दिसंबर।

जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के एक जंगल क्षेत्र से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पुलिस, राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के एक संयुक्त अभियान में द्वाचन तहसील के साउंदर गांव निवासी

तारिक हुसैन वानी को सोमवार की रात इखला पलामार जंगल में एक अस्थायी ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। आतंकीवादी को बाएं धर में गोली लगी थी और उसे तुरन्त किश्तवाड़ के जिला अस्पताल ले जाया गया। वानी 14 नवंबर से लापता था। उसके पास से एक 303 राइफल, एक मैगजीन और 64 कारतूस बरामद किए गए हैं।



फाइल फोटो

51 भगोड़े आर्थिक अपराधियों ने लगाया 17,900 करोड़ से ज्यादा का चूना

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (भाषा)।

आर्थिक अपराध कर देश छोड़कर भागने वाले 51 लोगों ने कुल मिलाकर 17,900 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है, सरकार ने मंगलवार को संसद को यह जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह टाकुर ने राज्यसभा में भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

मंत्रों ने कहा, 'सीबीआइ ने बताया है कि आज तक, 66 मामलों में 51 फरार और घोषित अपराधी अन्य देशों में भाग गए हैं।' उन्होंने कहा, 'सीबीआइ ने रिपोर्ट दी है कि इन मामलों में आरोपी व्यक्तियों द्वारा दी गई कुल लगभग 17,947.11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है।' उनसे पूछा गया था कि इन घटनाओं में कितनी रियायतें दी गई थीं या कर्ज माफ किए गए थे। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआइ ने सक्षम न्यायालयों में इन मामलों के संबंध में आवेदन दायर किए और जांच अथवा दूसरी कार्रवाई जारी है।

ईडी और सीबीआइ ने सक्षम न्यायालयों में इन मामलों के संबंध में आवेदन दायर किए और जांच अथवा दूसरी कार्रवाई जारी है। टाकुर ने कहा कि सीबीआइ, घोषित अपराधियों और फरार लोगों के संबंध में 51 प्रत्येक अनुरोधों पर काम कर रही है, जो विभिन्न चरणों में लंबित हैं।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क विभाग (सीबीआईसी) ने छह भगोड़े आर्थिक अपराधियों के बारे में रिपोर्ट की है जो अवैध रूप से देश छोड़ गए हैं।

एसपीजी कानून में संशोधन को संसद की मंजूरी

प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के बाद पांच साल तक सुरक्षा

केवल प्रधानमंत्री को विशिष्ट सुरक्षा घेरा

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (भाषा)।

संसद ने एसपीजी कानून में संशोधन करने वाले विधेयक को मंगलवार को स्वीकृति दे दी। इसके तहत प्रधानमंत्री तथा पद छोड़ने के पांच साल बाद तक पूर्व प्रधानमंत्री को यह विशिष्ट सुरक्षा घेरा प्रदान किया जाएगा।

सरकार ने यह साफ किया कि यह प्रस्तावित कानून गांधी परिवार के सदस्यों को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया है क्योंकि इसे लाने से पहले ही इस परिवार के तीन सदस्यों की सुरक्षा श्रेणी को एसपीजी से बदलकर जेड प्लस कर दिया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने एसपीजी (संशोधन) विधेयक बाकी पेज 8 पर



'हमारे नेताओं का जीवन जोखिम में डाला गया'

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (भाषा)।

कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बाकी पेज 8 पर

'प्रियंका की सुरक्षा में सेंध मामले में तीन सुरक्षाकर्मी निलंबित'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 दिसंबर।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्ढा के सुरक्षा घेरे में लगी सेंध मामले में तीन सुरक्षाकर्मीयों को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है। इस मसले को संसद के बाकी पेज 8 पर

गृह मंत्री ने कहा, राजोआना को कोई माफी नहीं

जनसत्ता ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली/चंडीगढ़, 3 दिसंबर।

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना के बारे में गृह मंत्री के बयान को शिरोमणि अकाली दल ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दल का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर उनसे इस मामले पर चर्चा करेगा।

सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य और बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू के एक 'दुर्भाग्यपूर्ण' प्रश्न के उत्तर में शाह ने यह जानकारी दी।

बिट्टू ने सवाल किया कि क्या राजोआना को माफी दी जा रही है? इस पर शाह ने कहा- मीडिया रिपोर्ट पर मत जाइए। कोई माफी नहीं की गई है। राजोआना बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी है।

इस बीच चंडीगढ़ से एक रिपोर्ट के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने अमित शाह के बयान को करार दिया। शिअद अध्यक्ष बाकी पेज 8 पर

मुंडे ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामलों को वापस लेने की मांग की

मुंबई, 3 दिसंबर (भाषा)।

राकांपा नेता और विधायक धनंजय मुंडे ने पुणे में कोरेगांव-भीमा हिंसा के संबंधित मामलों को वापस लिए जाने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागर रिफाइनरी परियोजना और आरे मेट्रो कारशेड प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के कुछ दिन बाद मुंडे ने यह मांग की।

भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित 'एलगाार परिषद' के सम्मेलन में दिए गए भड़काऊ भाषण के एक दिन बाद एक जनवरी, 2018 को पुणे जिले के

करतारपुर कॉरिडोर से फैसलाबाद जाते पकड़ी गई भारतीय युवती

लाहौर, 3 दिसंबर (एजेंसी)।

भारत की सिख महिला पाकिस्तान के करतारपुर दौरे के समय बिना वीजा के पाकिस्तानी व्यक्ति से मिलने के लिए फैसलाबाद जाने का प्रयास किया।

महिला ने करतारपुर कॉरिडोर से फैसलाबाद जाने के लिए पाकिस्तानी की एक महिला के परिमित का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के अधिकारियों ने महिला को भारत भेज दिया है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने महिला के दोस्त व उसकी मदद कर रहे दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें एक महिला है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि करीब 20 वर्ष की मंजीत कौर नवंबर के अंतिम हफ्ते में बाकी पेज 8 पर

चेन्नई के सुब्रमण्यम को श्रेय दिया 'नासा' ने चंद्रयान-2 लैंडर के हिस्से कई किलोमीटर तक बिखरे हुए हैं

भारतीय इंजीनियर ने खोजा लैंडर विक्रम का मलबा

वाशिंगटन, 3 दिसंबर (भाषा)।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' को चंद्रमा पर भारत की महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 परियोजना के विक्रम लैंडर का मलबा मिला है और एजेंसी ने इसका श्रेय चेन्नई के मैकेनिकल इंजीनियर पनमुगा सुब्रमण्यम को दिया, जिन्होंने इसे खोजने में मदद की।

नासा ने अपने 'लूनर रिस्कॉनाइसर्स ऑर्बिटर' (एलआरओ) से ली गई तस्वीर में अंतरिक्ष यान से टक्कर स्थल को और उस स्थान को दिखाया है जहां मलबा हो सकता है। लैंडर के हिस्से कई किलोमीटर तक लगभग दो दर्जन स्थानों पर बिखरे हुए हैं।

लैंडर विक्रम सितंबर में चंद्रमा की तहत पर उतरते दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विक्रम लैंडर की



सुब्रमण्यम ने एक ट्वीट में लिखा, 'नासा ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की तलाश का श्रेय मुझे दिया है।' मंदिरों के शहर मदुरै के इस निवासी ने कहा कि विक्रम के गिरने की जगह का पता लगाने के लिए उन्होंने दो लैपटॉप का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से उन्होंने उपग्रह द्वारा भेजी गई पहले और बाद की तस्वीरों का मिलान किया। वह हर दिन एक शीर्ष आईटी फर्म में काम करने के बाद रात 10 बजे से दो बजे तक और फिर ऑफिस जाने से पहले सुबह आठ बजे से 10 बजे तक आंकड़ों का विश्लेषण करते। उन्होंने करीब दो महीने तक इस तरह आंकड़ों का विश्लेषण किया।

सात सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की कोशिश नाकाम रही थी और लैंडिंग से कुछ मिनट पहले लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया था। नासा ने एक बयान में कहा कि उसने स्थल की एक तस्वीर 26 सितंबर को साझा की और लोगों से उस तस्वीर में लैंडर के मलबे को पहचानने बाकी पेज 8 पर

अलविदा खांसी

हर्बल कफ सिरप

खांसी

सर्दी

कफ

तुलसी
तुलसी एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक कीटाणुनाशक है।

पिप्पली
पिप्पली कफ को उत्पन्न होने से रोकता है।

वासा
वासा कफ को पतला करके बाहर निकालता है।

कुलंजन
कुलंजन सांस लेने में दिक्कत को दूर करता है।

यष्टीमधु
यष्टीमधु गले के रोगों में लाभदायक है।

एल्कोहल रहित

TOREX

तुलसी और शहद के गुणों सहित

Distributor contact : Delhi - Raj Ayurved Bhagirath Palace +91 92108 01700, 80764 36657
 RSM : +91 88821 71439 sales@torquepharma.com
 For more information, please contact : +91 97792 14455 / care@torquepharma.com

हैदराबाद बलात्कार और हत्या मामले को लेकर नाराजगी

मालीवाल की भूख हड़ताल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 दिसंबर।

हैदराबाद में हुई बलात्कार की घटना के बाद दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। यह हड़ताल जंतर मंतर पर शुरू हुई, जहां उनके साथ बड़ी संख्या में छात्राएं व महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उधर महिला आयोग की अध्यक्ष ने बलात्कार की घटनाओं को लेकर एक पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है।

जंतर मंतर पर अनशन शुरू करने से पूर्व स्वाति मालीवाल सबसे पहले राजघाट पहुंची और बापू महात्मा गांधी को नम्र आशीर्वाद देकर काफी देर प्रार्थना करने के बाद स्वाति अपने अनशन के लिए जंतर मंतर पहुंची। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब तक इन मांगों को पूरा नहीं करता जब तक वे अनशन नहीं तोड़ेंगी। हालांकि देर शाम दिल्ली पुलिस की ओर से एक ट्वीट जारी कर बताया गया कि स्वाति मालीवाल ने अपना धरनास्थल जंतर मंतर से हटाकर समता स्थल कर लिया है। उधर इस मामले को स्पष्ट करने की मांग करते हुए पुलिस ने कहा कि डीसीडब्ल्यू की पत्र लिखकर प्रदर्शन का विवरण, परिचयन के साधन, माइक्रोफोन के प्रबंध और इसमें शामिल होने वाले प्रदर्शकारियों की संख्या



सोशल मीडिया के जरिये पुलिस पर उठाए सवाल

सुबह साढ़े 9 बजे स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि पुलिस हमें जंतर मंतर पर नहीं बैठने दे रही है। रात भर पुलिस ने पूरा जंतर मंतर बैरिकेडिंग करके टेंट, माइक और टैल्फोन नहीं लगने दिया। साफ बोला है कि अनशन नहीं होने देंगे। देश में एक महिला शांति से अनशन भी नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को ऐसा क्या डर है और क्या सच में लोकतंत्र है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देर रात जानकारी दी कि पुलिस ने हजारों की संख्या में पुलिस तैनात की हे और इन्हें प्रदर्शन को खत्म करने के लिए भेजा गया है।

आज 30 दिसंबर को देशभर में नारी दिवस मनाया जाएगा।

के संबंध में जानकारी मांगी है। साथ ही उस हलफनामे की एक प्रति भी मांगी है जिसे सुप्रिंट कंट्रॉ के दिशानिर्देशों के अनुसार भरा जाना होता है। उन्होंने बताया कि विवरण का इंतजार किया जा रहा है। महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को बधाई देता हूं। इन मुद्दों में एक तरह की बात करनी चाहिए और एक स्वर में

बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सौनी मिश्रा मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए। हैदराबाद की घटना से सभी आहत हैं। इस मामले में सौनी मिश्रा भी मुख्यमंत्री के पास गई थी। इस प्रकार के मामलों में जो भी हो उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए।

आइआइएमसी की अधिक फीस के विरोध में प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 दिसंबर।

भारतीय जन संचार संस्थान (आइ आइएमसी) के विद्यार्थियों ने संस्थान में चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के अधिक शुल्क को लेकर मंगलवार को परिसर में प्रदर्शन किया और दोपहर बाद कक्षाओं का बहिष्कार किया। अधिक शुल्क के संबंध में करीब 30 विद्यार्थियों ने संस्थान के महानिदेशक केएस धतवालिया को पत्र भी लिखा है।

प्रदर्शन में शामिल एक विद्यार्थी का कहना है कि आइआइएमसी में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क बहुत अधिक है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि उनके परिवार की आय 70 हजार रुपए सालाना है और उनको परिवार में छह सदस्य हैं। उन्होंने बताया

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 3 दिसंबर।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने मंगलवार को फिर विद्यार्थियों को 12 दिसंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए कहा है। प्रशासन ने विद्यार्थियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो विद्यार्थी परीक्षाएं नहीं देता है, वह जेएनयू के अकादमिक नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहेगा।

इससे पहले जेएनयू प्रशासन की ओर से 17, 28 और 29 नवंबर को भी इस मामले में संकुलर जारी करते हुए विद्यार्थियों को चेताया था। एक महीने से अधिक से जेएनयू के विद्यार्थियों छात्रावास की शुल्क बढ़ोतरी और इसके नए नियमों को लागू करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि इसे वापस लिया जाए। प्रशासन का कहना है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन के कारण संस्थान में अकादमिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जो विद्यार्थियों अकादमिक गतिविधियों एवं नियमों, मानदंडों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानदंडों और अकादमिक कैलेंडर का पालन करना विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। इसके अनुसार

	मासम			
<i>तापमान</i> नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम फरीदाबाद				
अधिकतम	24.4 डि.से.	24.4 डि.से.	24.0 डि.से.	24.5 डि.से.
न्यूनतम	9.1 डि.से.	9.1 डि.से.	9.0 डि.से.	9.0 डि.से.

जनसत्ता, नई दिल्ली, 4 दिसंबर, 2019 4

खबरों में शहर

आइआइटी की छात्रा को किया सम्मानित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 दिसंबर।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली की छात्रा अंकिता गुलाटी को उपराष्ट्रपति एम वैकेया नायडू ने पंजाबसेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी-20 19 पुरस्कार से सम्मानित किया। मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर उन्हें यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। गुलाटी ने दिव्यांगों को आसानी से सिखाने के लिए एक डिजाइन वर्ल्डन रिसोर्स विकसित किया है। जो दिव्यांगों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से निर्माण किया गया है। अंकिता ने स्टार्टअप से प्रेरित होकर यह कार्य किया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को आगे आने का प्रयास करना चाहिए।

उद्घाटन



हंसराज स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया।

स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न

नई दिल्ली, 3 दिसंबर।
जनसत्ता संवाददाता

हंसराज स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिलशाद गार्डन का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम यमुना क्रीड़ा परिसर के सभागार में हुआ। समारोह में पूर्वी दिल्ली के सांसद गोतम गंभीर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के डीटी मेयर संजय गोयल, पूर्वी दिल्ली नगर में चेयरमैन स्टीडिंग कमेट्री ईडीएमसी सदीप कपूर, शाहदरा के जिलाध्यक्ष राम किशोर शर्मा मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रबंधक अरुण कुमार महाजन, प्रधान सुरेश कुमार महाजन, उप प्रधान प्रवीण मंगलान व संजीव महाजन, महासचिव अरुण कुमार महाजन, सचिव योगेश महाजन, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र महाजन और विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजु सिंह ने पुष्प मालाओं से किया। प्रबंधक अरुण महाजन ने मुख्य अतिथि का परिचय दिया। स्कूल के पूर्व व वर्तमान छात्र-छात्राओं को शिक्षा व खेल के क्षेत्र में और अन्य गतिविधियों में उत्तम प्रदर्शन के लिए अतिथियों ने पुरस्कार दिए। विशेष रूप से विद्यालय की 11वीं कक्षा की छात्रा प्रगति को तीरदाजी में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य श्रीमती अंजु सिंह ने विद्यालय की 2018-19 की वार्षिक गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। मंच का संचालन आकांशा आर्या एवं मुद्द गुप्ता ने किया।

शिक्षण में खेलकूद की अहम भूमिका : अनिक जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 3 दिसंबर।
विकास नगर रिश्त पायनियर कमल कॉन्वेंट स्कूल में सालाना पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें कई विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। स्कूल के प्राचार्य अजय वित्तारी के मुताबिक शिक्षाविद वेद टंडन और अनिक कुमार (डीडीई) ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। अनिक कुमार ने जहां शिक्षण में खेलकूद की अहम भूमिका बताई वहीं वेद टंडन ने कहा कि आज का दौर सामान्य शिक्षण वाला नहीं है। विशिष्ट और तकनीकी दक्षता को जरूरी बताया।

संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम आयोजित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 दिसंबर।
गाजियाबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ने प्राचीन पद्धतियों को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करते हुए लोगों को शारीरिक आरंभ करने के लिए कार्यक्रम किया। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम हुआ। कहा गया कि मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को शामिल किए बिना हम संपूर्ण स्वास्थ्य को नहीं पा सकते।

आज के कार्यक्रम

आइफैक्स : फोटो कला प्रदर्शनी, आइफैक्स, एक-रफ़ी मार्ग, सुबह 11 बजे से, पांच दिसंबर तक।
जापानी फाउंडेशन : कार्यशाला ‘हार्मनी’ का आयोजन, पांच ए. रिंग रोड लाजपत नगर चार, सुबह 10 बजे से, 21 दिसंबर तक।

तदर्थ शिक्षकों की बहाली के लिए आज से डीयू में हड़ताल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 3 दिसंबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शिक्षक तदर्थ शिक्षकों की बहाली और उनके वेतन जारी करने की लेकर बुधवार से हड़ताल पर रहेंगे। इस समय डीयू की परीक्षाएं हो रही हैं और बुधवार से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू होना है। इस हड़ताल का आह्वान डीयू शिक्षक संघ की ओर से किया गया है।

वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोकने का वादा करते हुए शिक्षकों से अपील की है कि वे परीक्षा और मूल्यांकन के कार्य को जारी रखें। बूटा उपाध्यक्ष डॉ आलोक पांडेय ने बताया कि प्रशासन की मनमानी के खिलाफ चार दिसंबर से हड़ताल बुलाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक गु्रवार को सुबह 11 बजे उत्तरी परिसर में गेट नंबर 4 के सामने कला संकाय पर मिलेंगे।

आइपी विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह

के अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल सिसौदिया, आइपी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ महेश वर्मा, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव, सीएसआइआर के पूर्व डीजी प्रोफेसर समीर के. ब्रह्मचारी समेत विश्वविद्यालय के तमाम लोग मौजूद रहे।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय का कुलगीत भी गाया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना के 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तैयार की गई स्मारिका का भी लोकार्पण किया गया। दीक्षांत समारोह में कुल 68,662 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई जिसमें 108 पीएचडी, 542 एमबीबीएस, 11,683 स्नातकोत्तर, 55,367 स्नातक,

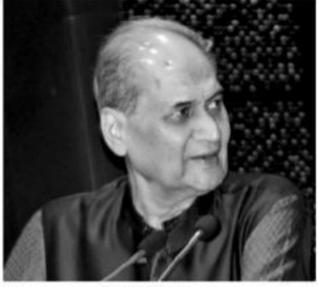
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दौड़ेगी एक्वा मेट्रो, कैबिनेट ने दी मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 3 दिसंबर।

सेक्टर-71 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-पांच तक प्रस्तावित एक्वा मेट्रो विस्तार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कुल 14.95 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो परियोजना का लाभ ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और गौड़ सिटी आदि इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। यह विस्तार दो चरणों में किया जाएगा। इस पर 2682 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के साथ तीन माह में निर्माण कार्य शुरू कराने की योजना है। सेक्टर-71 से नॉलेज पार्क-पांच तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट (डीपीआर) को

नई दिल्ली



राहुल बजाज

अध्यक्ष, जमनालाल बजाज फाउण्डेशन

मूलभूत मानव मूल्य शाश्वत हैं। अपनी ही नैतिकता में तपकर, लालच और अपने अहम् के कारण हमारी आँखों पर परदा पड़ सकता है। किंतु अंततः हमने कितने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, यही हमारे जीवन को मापने का पैमाना बनता है। इस पैमाने के अनुसार हमारे सम्मान मूर्ति अत्यंत धनी हैं और हम सभी के साथ अपनी समृद्ध भावनाओं को साझा करने के लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये संसार आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से एक कठिन स्थान है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सतत एक नया संघर्ष जन्म लेता रहता है। हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए, और साथ ही हमें बहुत सारी आकांक्षाएं भी नहीं रखनी चाहिए। परिवर्तन तो अनपेक्षित तरीकों से ही होता है। हमें सही मार्ग को कभी त्यागना नहीं चाहिए। अपने जीवन में हमें इसी पथ पर चलने और इसे प्रतिबिंबित करने का प्रयास करना चाहिए, फिर चाहे हम कितने ही निर्बल क्यों न हों।

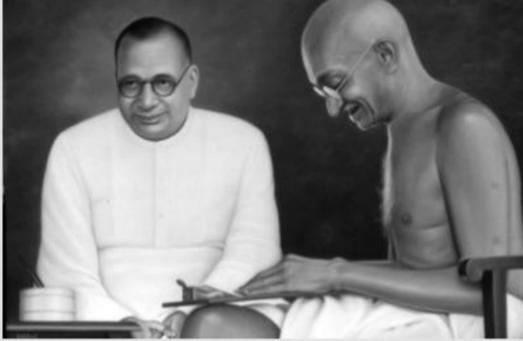
भवानी शंकर कुसुम
(राजस्थान)

आज मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या मैं देश के ऐसे महान सपूत जमनालालजी बजाज के नाम पर गठित पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र हूँ? मैं उनके त्याग, गरिमामय व्यक्तित्व और सतत कर्मशील जीवन के प्रति नतमस्तक हूँ। गांधीजी से मुझे सोचने की शक्ति, कर्म की प्रेरणा और सार्थक ढंग से जीवन जीने का मंत्र मिला। ईशावास्योपनिषद, जिसे गांधीजी भारतीय संस्कृति का मूल आधार मानते थे, का एक श्लोक है- 'कुर्यन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समाः' अर्थात् मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की कल्पना करनी चाहिए। इसलिये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन तथा महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही जीवन का उद्देश्य बनाया है।

मोहम्मद इमरान खान मेवाती
(राजस्थान)

प्रतिभा तो मानव जाति की जमा पूँजी होती है, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पढ़ाई का अवसर तो सबको समान मिलने चाहिए। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके ज़रिए किसी परिवार, समाज या किसी तबके को, जो पिछड़ रहा है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से अन्य मसले जैसे सामाजिक बुराईयां स्वतः ही काबू में होने लगती हैं। हम सभी को इस दिशा में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम 'पाने वाले' से 'देने वाले' कैसे बनें।

जमनालाल बजाज पुरस्कार - 2019 द्वारा गांधीवादी 'योद्धाओं' का सम्मान



“मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि जमनालालजी ने एक पाई भी अनीति से नहीं कमाई, और जो कमाया वह संपूर्णतः जनता जनार्दन के लिए ही खर्च किया।”

- महात्मा गांधी



रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार - 2019 प्राप्त करते हुए भवानी शंकर कुसुम (राजस्थान)।



ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन हेतु जमनालाल बजाज पुरस्कार - 2019 प्राप्त करते हुए मोहम्मद इमरान खान मेवाती (राजस्थान)।



महिलाओं और बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार - 2019 प्राप्त करती शाहीन मिस्त्री (महाराष्ट्र)।



विदेशों में गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार - 2019 प्राप्त करती सोनिया डेटो (मेक्सिको)।



(बाएँ से) मिनल बजाज (मानद निदेशक - जमनालाल बजाज फाउण्डेशन), डॉ. मरिअम्मा ए. वर्गीस (अध्यक्ष - महिला एवं बाल कल्याण पुरस्कार), शाहीन मिस्त्री, धीरजलाल मेहता (अध्यक्ष - रचनात्मक कार्य पुरस्कार), भवानी शंकर कुसुम, डॉ. आर. ए. मशेलकर, एफआरएस (अध्यक्ष - परामर्शदाता परिषद), सद्गुरु (संस्थापक, ईशा फाउण्डेशन), राहुल बजाज (अध्यक्ष - जमनालाल बजाज फाउण्डेशन), मोहम्मद इमरान खान मेवाती, डॉ. अनिल काकोडकर (अध्यक्ष - विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार), सोनिया डेटो, अनु आगा (अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार), मधुर बजाज (न्यासी, अध्यक्ष, जमनालाल बजाज फाउण्डेशन)

परामर्शदाता परिषद

डॉ. आर. ए. मशेलकर, एफआरएस (अध्यक्ष), अनु आगा, राधा भट्ट, डॉ. फिरोज़ा गोदरेज, डॉ. सुदर्शन आर्यंगर, डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. एस. एन. सुब्बा राव, संजित (बंकर) रॉय, सुप्रिया सुले, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, डॉ. मरिअम्मा ए. वर्गीस, मिनल बजाज (मानद निदेशक)।

पूर्व मुख्य अतिथिगण

एन. संजीव रेड्डी, दादा धर्माधिकारी, इंदिरा गाँधी, डॉ. नोरमन बोरलोग, जेम्स कॅलाघन, आर. वेंकटरामन, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला, डॉ. शंकर दयाल शर्मा, राजीव गाँधी, स्वामी रंगनाथानंद, डॉ. हार्बर्ट शामबेक, सी. सुब्रह्मण्यम, के.आर. नारायणन, पांडुरंग शास्त्री आठवले, दलाई लामा, एच.डी. देवे गौड़ा, मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. पी.सी. एलेक्जेंडर, कृष्णकांत, डॉ. मनमोहन सिंह, भैरोसिंह शेखावत, विरेन जे. शाह, डॉ. एल. एम. सिंघवी, प्रो. अमर्त्य सेन, एन. आर. नारायणमूर्ति, श्री श्री रविशंकर, हामिद अंसारी, स्वामी बाबा रामदेव, प्रतिभा पाटिल, मुरारी बापू, डॉ. न्यायमूर्ति सी.एस. धर्माधिकारी, प्रणव मुखर्जी, कैलाश सत्यार्थी, राजमोहन गांधी, अरुण जेटली और एम. वैकैया नायडु।



न्यास मंडल (बायें से) कैलाश सत्यार्थी, राहुल बजाज (अध्यक्ष), धीरजलाल मेहता, मधुर बजाज।



जमनालाल बजाज फाउण्डेशन

बजाज भवन, जमनालाल बजाज मार्ग, 226 नरिमन पॉइंट, मुंबई 400 021 भारत.

Phone: 022-2202 3626. Email: info@jambhajibajajfoundation.org,

secretary@jambhajibajajfoundation.org

nominations@jambhajibajajfoundation.org

(ONLY for Nomination inquiries & submissions)

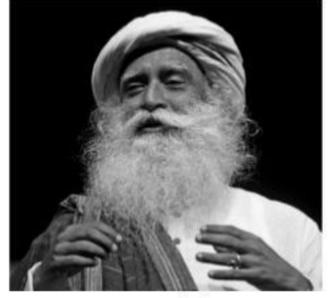
Visit www.jambhajibajajfoundation.org, www.jambhajibajajawards.org

www.bajajgroup.com, https://www.facebook.com/JBF Mumbai

पुरस्कार - 2020 के लिए नामांकन आमंत्रित हैं.

http://jambhajibajajawards.org/nomination-forms

(For ONLINE submissions)

मुख्य अतिथि
सद्गुरु

संस्थापक, ईशा फाउण्डेशन

स्वयं में परिवर्तन लाए बिना समाज को बदलना, दुनिया को बदलना बस एक कोरी बात ही रहेगी। अब समय आ गया है कि इसमें व्यक्ति अपना योगदान दे, समाज कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। समाज तो हम सभी के अपने-अपने स्वभावों को मिलाकर बनता है। यदि हम इसे शांतिपूर्ण नहीं बनाते हैं, यदि हम इसे अपने आपसी विवादों से मुक्त नहीं रखते हैं तो ये चर्चा अंतहीन रूप से चलती ही रहनेवाली है।

यदि आप और मैं यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं तो हमें शांति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तब तो सारा संसार ही शांतिपूर्ण प्रतीत होगा। लेकिन यदि हम इस स्थिति को लाना चाहते हैं तो आपको और मुझे ये देखना होगा कि हम अपने भीतर ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे स्वभाव को आनंदमय बना सके।

महात्मा गांधी का संदेश भी यही था। वे देश या लोगों से जो अपेक्षा रखते थे, उसका प्रयोग अपने तरीके से सर्वप्रथम स्वयं के साथ करते थे कि क्या वे जो दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं वह पूर्ण सत्य है।

शाहीन मिस्त्री
(महाराष्ट्र)

मैं चाहती हूँ कि मैं अधिक बच्चों के लिए और भी अधिक काम करती रहूँ क्योंकि ये कहानियाँ न मैंने सुनी हैं और न ही मेरी उपज हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सच्चाई को मैं भलीभाँति जानती हूँ। यदि हमारे बच्चे कल नहीं बल्कि आज के सपने देखें। यदि वे प्रस्तुत स्थितियों में नहीं बल्कि अपेक्षित परिस्थिति को निर्मित करने में विश्वास करें। यदि उन्हें स्कूल से नहीं बल्कि जीवन से सीखने के अवसर मिलें। यदि वे खुद से और अपने आस पास हर किसी से प्रेम करें तो ये दुनिया खूबसूरत बन जाएगी- अधिक सुशील, उदार, प्रमाणिक हो जाएगी। दुनिया से दुःख दूर होगा और सुख के प्रकाश से भर जाएगी।

सोनिया डेटो
(मेक्सिको)

हमारे भीतर नष्ट करने के बजाय सृजन करने की आकांक्षा पैदा होती है, और इसके साथ हम समग्रतः मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से अहिंसा या प्रेम की साधना में स्वयं को तथा एक-दूसरे को शिक्षित करने के लिए तत्पर होते हैं, जो इस धरती पर शांति के उत्थान का सबसे प्रभावशाली साधन है। सभी लोगों के कल्याण एवं स्वायत्तता की दिशा में इस सामूहिक यात्रा में हम सत्य पर जोर देने का आह्वान करते हैं, ताकि अहिंसा की शक्ति को दृश्यमान बनाया जा सके। वैश्विक सहभागिता के इस रंगमंच पर हम सभी अहिंसा का अभिनय करने वाले कलाकार हो सकते हैं।

महंगा परिचालन

अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर अभी बहसें चल ही रही हैं कि रेलवे की हालत ठीक न होने के आंकड़े ने सरकार के लिए नई चिंता पैदा कर दी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि 2018–19 के दौरान रेलवे की कमाई और परिचालन खर्च में बहुत कम अंतर था। उसे सौ रुपए कमाने के लिए अट्‍टानबे रुपए चौवालीस पैसे खर्च करने पड़े। यह पिछले दस सालों में सबसे अधिक परिचालन खर्च है। यह तब है, जब रेलवे ने पिछले सालों में यात्री और माल भाड़े में बढ़ोतरी की है। इस दौरान कई नई गाड़ियां भी चली हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ी है। फिर भी उसकी कमाई और परिचालन खर्च में बहुत कम का अंतर रह गया है, तो यह निस्संदेह चिंता का विषय है। जिस वर्ष का रेलवे के परिचालन पर खर्च का लेखाजोखा पेश किया गया है, उस वर्ष उसने अपनी कुछ ग्राहक कंपनियों से अग्रिम शुल्क ले रखा था, वरना उसके लिए अपना खर्च संभालना मुश्किल होता। इसलिए सीएजी ने सुझाव दिया है कि रेलवे को अपनी आंतरिक आय बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सकल बजटीय प्रावधान पर निर्भर न रहना पड़े।

रेलवे की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत माल ढुलाई है। उसके बाद यात्री भाड़ा और फिर कुछ आमदनी रेलवे स्टेशनों पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दी गई जगहों के किराए से हो जाती है। पिछले कई सालों से रेलवे को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने का दम भरा जा रहा है। इसमें रेलवे स्टेशनों की मरम्मत, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने और उनमें सुरक्षा और यात्री सुविधाएं बेहतर बनाने का संकल्प दोहराया जाता रहा है। ऐसे में जाहिर है कि परिचालन खर्च बढ़ने से रेलवे के लिए इन पक्षों पर आगे कदम बढ़ाने के लिए काफी सोचना पड़ेगा। पहले ही नई पटरियां बिछाने, पुराने पुलों की जगह नए पुल बनाने, रेल लाइनों के विद्युतीकरण, गाड़ियों में टक्कररोधी उपकरण लगाने आदि जैसी रेलवे की अनेक परियोजनाएं लंबे समय से लटकी पड़ी हैं। कमाई न हो पाने से नई परियोजनाएं शुरू करना तो दूर, रुकी हुई परियोजनाओं को गति दे पाना ही कठिन होगा।

रेलवे की कमाई घटने की कुछ वजहें समझी जा सकती हैं। इसका सीधा संबंध अर्थव्यवस्था की सुस्ती से है। छिपी बात नहीं है कि औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन काफी घटा है। वाहन और कपड़ा उद्योग जैसे कई क्षेत्रों पर आर्थिक मंदी की बहुत बुरी मार पड़ी है। स्वाभाविक ही इससे रेलवे की माल ढुलाई पर असर पड़ा है, जो कि उसकी कमाई का बड़ा जरिया है। यानी जब तक औद्योगिक क्षेत्र में तेजी नहीं आती, रेल के पहियों में भी सुस्ती बनी रहेगी। जाहिर है, इस सुस्ती से पार पाने के लिए रेलवे को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। उनमें से पहला कदम यही हो सकता है कि वह अपने भाड़े और किराए में बढ़ोतरी करे। मगर इसका सीधा असर मुसाफिरों पर पड़ेगा। लोग पहले ही महंगाई से परेशान हैं, रेल भाड़े में बढ़ोतरी उन पर अतिरिक्त बोझ साबित होगी। यों रेलवे कई स्टेशनों के रखरखाव की जिम्मेदारी निजी हाथों को सौंप रहा है। उससे उसका खर्च कुछ कम हो सकता है। मगर मुसाफिरों की जेब पर उसका भार पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे सार्वजनिक परिवहन का बड़ा तंत्र है, अगर उसकी स्थिति सुधारने का प्रयास जल्दी नहीं किया गया, तो यह सरकार की बड़ी विफलता साबित होगी।

हादसों की सड़क

राज्यसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सड़क हादसों पर जो तस्वीर सामने रखी गई, उससे फिर यह सवाल उठा है कि क्या केवल कानूनों को ज्यादा सख्त बनाना किसी मसले से निपटने का अकेला जरिया हो सकता है! करीब सत्र बर महीने पहले ही सरकार ने हादसों में कमी लाने के मकसद से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों से लैस मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी। मकसद यही था कि कानूनी सख्ती से लोगों में वाहन चलाते समय बच काम करेगा और इस तरह सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा। मगर हकीकत यही है कि लोग वाहन चलाते समय मनमानी करते हैं और कानूनी सख्ती का भय उनमें कम ही होता है। ऐसे चालकों की संख्या काफी है, जो यातायात नियमों का पालन करना अपनी शान के खिलाफ और मनमाने तरीके से गाड़ी चलाना अपना अधिकार समझते हैं। पर सवाल है कि इस तरह की गैरजिम्मेदारी और लापरवाही से वाहन चलाने का हासिल आखिर क्या है?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सड़क हादसों में मामूली कमी दर्ज की गई है, लेकिन अफसोसजनक है कि जितनी भी दुर्घटनाएं हुईं, उनमें मरने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उनके मुताबिक इसकी मुख्य वजह सड़क इंजीनियरिंग संबंधी खामियां हैं। उनका वह आकलन सही हो सकता है। सड़क पर जो लोग वाहन चलाते हैं, उन्हें उन खामियों के मद्देनजर सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन क्या यह जरूरी नहीं था कि अगर सड़कों में ही ऐसी गड़बड़ियां हैं, जो हादसों की वजह बनती हैं, तो उनके बारे में हर स्तर पर जागरूकता फैलाई जाए, जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि लोग सावधानी बरतें? सड़कों पर ऐसी कई जगहें होती हैं, जहां विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, सड़क किनारे बोर्ड पर निर्देश भी लिखा होता है, लेकिन कई वाहन चालकों को उन निर्देशों पर गौर करना जरूरी नहीं लगता। जबकि बेहद मामूली लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन जाती है और उसमें लोगों की नाहक जान चली जाती है। पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच देश भर में होने वाले सड़क हादसों में कुल एक लाख बारह हजार चार सौ उनसठ लोगों की मौत हो गई और साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग घायल हुए।

विचित्र है कि भारत में दुनिया भर के कुल वाहनों का केवल तीन फीसद है, लेकिन सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद के मामले में यह अच्चल है। दरअसल, एक बड़ी चिड़बना वाहन चलाने वालों के भीतर खुद है। तय रफ्तार के नियम का पालन करना, शराब पीकर वाहन न चलाना, लेन में रहना, वाहन चलाते समय सजग रहना जैसे कुछ यातायात नियमों का ही पालन कर लिया जाए, तो सड़क हादसों में काफी कमी लाई जा सकती है। फिर दुर्घटना की स्थिति में अगर सरकार समय पर घायलों को इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था कर दे, तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा, वाहन चालकों को यह समझने की जरूरत है कि नियमों का पालन न केवल सुचारु यातायात व्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के साथ-साथ खुद का जीवन भी सुरक्षित रहने के लिहाज से अनिवार्य है। अच्छी सड़कें आधुनिक यातायात व्यवस्था के लिए जरूरी हैं, लेकिन उन पर वाहन चलाने का सलीका अगर न हो तो वही सड़कें जानलेवा साबित हो जाती हैं।

कल्पमेधा

किसी देश की शक्ति छोटे विचारों के बड़े आदमियों से नहीं, बल्कि बड़े विचारों के छोटे आदमियों से बनती है।

–स्वामी रामतीर्थ

अखिलेश आर्यदु

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।अखिलेश आर्यदु का पेशा व्यवसायिक है।अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

लोगों को यह भी नहीं मालूम कि आंखों को चौंधिया देने वाली ये बतियां उनकी उम्र को कम करने की वजह बन रही हैं।
लोगों के लिए तो पार्को, गलियों और सड़कों पर बतियों का होना विकास का पैमाना है। मगर इस तथाकथित विकास के पैमाने में उनकी जिंदगी का पैमाना गड़बड़ा रहा है, यह किसी को नहीं मालूम।

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण से पैदा होने वाली समस्याओं से लोग वाकिफ हैं। इनके चलते होने वाली बीमारियां पहले ही चुनौती बनी हुई हैं। इनका असर खेती-किसानी से लेकर सामान्य जन-जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए इन प्रदूषणों को कम करने की कवायदें भी विश्व स्तर पर जारी हैं। मगर प्रकाश प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के बारे में लोग नहीं जानते या इस तरफ़ अभी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद इसलिए कि दूसरे प्रदूषणों की तरह इस प्रदूषण के प्रभाव भयावह रूप नहीं ले पाए हैं। इसलिए इस खतरे के प्रति लोग आंख मूंदे हुए हैं। दक्षिण कोरिया स्थित सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर क्यांग-बोक मिन के मुताबिक रात में बाहरी यानी आउटडोर और कृत्रिम प्रकाश की तीव्रता का नौद की दवाओं से गहरा रिश्ता है। अध्ययन के मुताबिक रात में घर के बाहर के तेज

प्रकाश का असर नौद पर पड़ता है। इससे अनिद्रा की समस्या बढ़ रही है। इसलिए लोग नौद के लिए दवाओं का सेवन करते हैं। इससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में जबदस्त कमी देखी जा रही है और लोगों की औसत आयु में कमी आ रही है।

प्रकाश प्रदूषण एक ऐसी नई समस्या है, जिसका समाधान निकट भविष्य में संभव नहीं दिखाई देता, बल्कि इस समस्या के दिनौदिन और बढ़ने के आसार हैं। इसकी वजह यह है कि लगातार नए-नए शहर बसाए जा रहे हैं। शहरों में सुरक्षा-व्यवस्था ठीक रहे, इसलिए सड़कों, पार्को, व्यावसायिक परिसरों में ऊंचे खंभों पर तेज रोशनी वाली बतियां उपयोग की जाने लगी हैं। इसके अलावा जगह-जगह तेज चमक बिखेरने वाले होंडिंगों और साइनबोर्डों का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चकाचौंध कर देने वाली ये लाइटें सेहत पर किस तरह और कितना असर डाल रही हैं, इस पर नगरपालिका या सरकार को सोचने का वक़्त नहीं है। आमतौर पर आम लोग इस बाबत सोचते ही नहीं हैं। बल्कि सड़कों और घरों के बाहर गलियों में अगर बतियां न हों, तो उसके लिए आंदोलन तक पर उतर आते हैं। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि आंखों को चौंधिया देने वाली ये बतियां उनकी उम्र को कम करने की वजह बन रही हैं। लोगों के लिए तो पार्को, गलियों और सड़कों पर बतियों का होना विकास का पैमाना है। मगर इस तथाकथित विकास के पैमाने में उनकी जिंदगी का पैमाना गड़बड़ा रहा है, यह किसी को नहीं मालूम। यहाँ तक कि पढ़े-लिखे लोग भी तेज रोशनी को ही तरक्की का पर्याय मानते हैं।

अनेक अध्ययनों से यह तथ्य बहुत पहले सामने आ चुका था कि शहरों, पर्यटन स्थलों, जंगल सफारी आदि में रात को जलने वाली तेज बतियों की वजह से वहां रहने वाले पक्षियों और दूसरे चन्य जीवों के स्वाभाविक जीवन चक्र पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उनकी नौद में बाधा उत्पन्न होती है, इससे उनकी प्रजनन क्षमता घट रही है। इस वजह से अनेक पक्षियों और वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। मगर उन अध्ययनों के निष्कर्षों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। फिर यह सोचने की जरूरत नहीं समझी गई कि अगर वन्य जीवों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो मनुष्य पर भी जरूर कुछ प्रभाव पड़ता होगा। मगर चकाचौंध को विकास का पर्याय मानने वाली व्यवस्थाओं ने इसे कोई गंभीर समस्या नहीं माना।

बात को बदल दिया। मैंने सोचा कि दूसरों से लड़ते-झगड़ते उसने खुद को ही शायद उलझ लिया है। मुझे लगता है ‘जैसे को तैसा’ की कहावत को गलत तरह से समझने से हमें बचना चाहिए। यह सोचना कि किसी ने हमारा बुरा किया तो हम भी उसके साथ बुरा करेंगे, गलत है। उसकी प्रकृति से वह खुद ही अपने लिए दुख के बीज बो रहा है। सामने वाले के जैसा सम व्यवहार करके हम खुद की प्रकृति को भी अनजाने में बदल रहे होते हैं। इसके विपरीत असल में हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते हैं। ऐसे में कम से कम हम एक आदर्श व्यवहार का उदाहरण तो अप्रत्यक्ष रूप से सामने वाले को दे ही रहे होते हैं, जो कहीं न कहीं उसके मन को जरूर स्पर्श करेगा। इसके अलावा, दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में अपनी ऊर्जा और समय गंवाने से अच्छा है, वह समय और ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगाई जाए।

मेरी दोस्त की तरह ही मनुष्य के व्यवहार में बदलाव होने के कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जिनके चलते व्यक्ति का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। जब कभी कोई दिशाहीन हो जाता है तो उसे अच्छी सलाह, अच्छे वातावरण और अच्छी

अपराध और दंड

दरआबाद में पशु चिकित्सक युवती से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना से देश में गुस्से का माहौल है।होना भी चाहिए. आखिर आधी आबादी की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन इस सबके बाद खबरिया टीवी चैनलों में एक चर्चा शुरू हुई कि क्या बलात्कार करने वाले को भीड़ के हवाले कर दिया जाए या भारत में अरब देशों जैसे कानूनों को लाया जाए जिसके तहत मुजरिम का सर काट दिया जाता है। ये गुस्से से उपजी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं लेकिन कानूनसम्मत और व्यावहारिक नहीं।

हमें ऐसे बयान देते वक्त सिर्फ एक पहलू को नहीं देखना चाहिए, यह गैरजिम्मेदाराना है। अगर हम अरब देशों के नियम-कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि कई अरब देशों में महिलाओं के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में महिलाओं को बिना पुरुष के निकलने की आजादी के लिए एक अभियान चलाना पड़ा था। अरब देशों में महिलाओं को अपनी आजादी के लिए समय-समय पर लड़ना पड़ता है लेकिन इसके विपरीत भारत ऐसा लोकतंत्र है जहां महिलाओं को बराबर को अधिकार दिए गए हैं। हम उनसे भारत की तुलना या भारत में उन देशों के नियमों को लागू नहीं कर सकते जहां मुजरिम को पत्थर से मार देने का कानून सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी लागू है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं?

अभिप्राय यह नहीं कि बलात्कारियों को सजा न मिले, लेकिन देश में हम आरोप सिद्ध होने का इंतजार किए बिना ही कैसे किसी को भीड़ के हवाले कर सकते हैं या मार सकते हैं? नगालैंड, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के अलग-अलग तीन ऐसे मामलों में आरोपियों को भीड़ ने निर्ममता से मार दिया था लेकिन बाद में जांच में उन तीनों के निर्दोष होने की बात सामने आई। ऐसे किसी

उम्र घटाती रोशनी

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक और अर्थशास्त्री प्रो माइकल ग्रीनस्टोन के मुताबिक वैश्विक आबादी का पचास फीसद या 5.5 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां प्रदूषण की समस्या डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर गई है। गौरतलब है कि भारत और चीन में दुनिया की छ्तीस प्रतिशत आबादी रहती है। दोनों देशों में वायु, ध्वनि, जल, मृदा और प्रकाश प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक इन दोनों देशों में रहने वाले लोगों की औसत उम्र में तिहत्तर फीसद की कमी आई है। उड़ती धूल से जहां सिर दर्द, बुखार, नेत्ररोग, चर्मरोग, श्वासरोग और एलर्जी जैसी समस्याएं विकट होती जा रही हैं, वहीं पर प्रकाश प्रदूषण के कारण अनिद्रा, नेत्ररोग, हृदयरोग और मानसिक रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्राकृतिक प्रकाश को

जिंदगी का कभी सहचर माना जाता था, वह जब कृत्रिम रूप से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, तो हमारे लिए समस्या पैदा करने वाला बन जाता है, नए शोध और सर्वेक्षण तो यही कह रहे हैं।

इसी तरह मृदा प्रदूषण से, जिसमें उड़ती धूल की समस्या सबसे ज्यादा है, सब्जियां, फलों, खाद्यान्न और दूसरी खेत में पैदा होने वाली वस्तुएं प्रदूषित हो रही हैं। ऐसी वस्तुओं के सेवन से पेट, मस्तिष्क, त्वचा, आंख, किडनी, लीवर पर अत्यंत घातक असर पड़ रहा है। असमय में समाज के हर आयु वर्ग का व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होने लगा है। कुछ साल पहले यह अध्ययन भी सामने आया था कि गंगा और यमुना जैसी नदियों के प्रदूषित होते जाने की वजह से उनके किनारे के गांवों में मृदा प्रदूषण तेजी से बढ़ा है और उसके चलते वहां कई तरह की

असह्यताएं पैदा हो रही हैं, जो आमतौर पर शहरों की मानी जाती थीं।

पाराली जलाने से हवा और सेहत तो चौपट हो ही रही है, जमीन की उर्वरा-शक्ति में जबदस्त कमी देखी जा रही है। सर्वेक्षण के मुताबिक भूमि में अस्सी फीसद तक सल्फर, नाइट्रोजन और बीस फीसद अन्य

जैसे को तैसा नहीं

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

जब कभी हमारा सामना ऐसे लोगों और वातावरण से हो, जहां संवाद, आचरण और समझ का स्तर कमतर, संकुचित लगे, तब हमें उसी स्तर तक जाने से बचना चाहिए। बल्कि ऐसे में अपने विचारों की श्रेष्ठता, व्यावहारिक और विनम्र आचरण के आदर्श स्थापित कर उस दूषित, कटु वातावरण को बेहतर

बनाने का प्रयास करना उचित कहा जा सकता है। जहां विचार अशुद्ध है और सत्य का अभाव होता है, अक्सर वहां संवाद आक्रामक और आवाज बुलंद होती है। वहीं जहां ज्ञान और विवेकशीलता होगी, वहां बड़े-बड़े मसले भी बहुत शांति और विनम्रता से हल हो जाते हैं।

ऐसी बात नहीं है कि वाद-विवाद, मतभेद हमेशा ही विध्वंसकारी या घातक होते हैं।विवेकपूर्ण बहसों, विमर्शों और विचारों के मंथन से ही आखिर में कुछ बेहतर निकल कर आता है। पर जब वाद-विवाद, स्वार्थ, गुस्से और अहंकार से दूषित हो जाए और हर व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो जाए, नए नजरिये का स्वागत न हो, तो वह सिर्फ कलह कहा जाएगा। वह घातक है। वहां सब

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

यूनिवर्सिटी ऑफ़ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक और अर्थशास्त्री प्रो माइकल ग्रीनस्टोन के मुताबिक वैश्विक आबादी का पचास फीसद या 5.5 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां प्रदूषण की समस्या डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर गई है। गौरतलब है कि भारत और चीन में दुनिया की छ्तीस प्रतिशत आबादी रहती है। दोनों देशों में वायु, ध्वनि, जल, मृदा और प्रकाश प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक इन दोनों देशों में रहने वाले लोगों की औसत उम्र में तिहत्तर फीसद की कमी आई है। उड़ती धूल से जहां सिर दर्द, बुखार, नेत्ररोग, चर्मरोग, श्वासरोग और एलर्जी जैसी समस्याएं विकट होती जा रही हैं, वहीं पर प्रकाश प्रदूषण के कारण अनिद्रा, नेत्ररोग, हृदयरोग और मानसिक रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्राकृतिक प्रकाश को

जिंदगी का कभी सहचर माना जाता था, वह जब कृत्रिम रूप से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, तो हमारे लिए समस्या पैदा करने वाला बन जाता है, नए शोध और सर्वेक्षण तो यही कह रहे हैं।

इसी तरह मृदा प्रदूषण से, जिसमें उड़ती धूल की समस्या सबसे ज्यादा है, सब्जियां, फलों, खाद्यान्न और दूसरी खेत में पैदा होने वाली वस्तुएं प्रदूषित हो रही हैं। ऐसी वस्तुओं के सेवन से पेट, मस्तिष्क, त्वचा, आंख, किडनी, लीवर पर अत्यंत घातक असर पड़ रहा है। असमय में समाज के हर आयु वर्ग का व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होने लगा है। कुछ साल पहले यह अध्ययन भी सामने आया था कि गंगा और यमुना जैसी नदियों के प्रदूषित होते जाने की वजह से उनके किनारे के गांवों में मृदा प्रदूषण तेजी से बढ़ा है और उसके चलते वहां कई तरह की

असह्यताएं पैदा हो रही हैं, जो आमतौर पर शहरों की मानी जाती थीं।

पाराली जलाने से हवा और सेहत तो चौपट हो ही रही है, जमीन की उर्वरा-शक्ति में जबदस्त कमी देखी जा रही है। सर्वेक्षण के मुताबिक भूमि में अस्सी फीसद तक सल्फर, नाइट्रोजन और बीस फीसद अन्य

जैसे को तैसा नहीं

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

जब कभी हमारा सामना ऐसे लोगों और वातावरण से हो, जहां संवाद, आचरण और समझ का स्तर कमतर, संकुचित लगे, तब हमें उसी स्तर तक जाने से बचना चाहिए। बल्कि ऐसे में अपने विचारों की श्रेष्ठता, व्यावहारिक और विनम्र आचरण के आदर्श स्थापित कर उस दूषित, कटु वातावरण को बेहतर

बनाने का प्रयास करना उचित कहा जा सकता है। जहां विचार अशुद्ध है और सत्य का अभाव होता है, अक्सर वहां संवाद आक्रामक और आवाज बुलंद होती है। वहीं जहां ज्ञान और विवेकशीलता होगी, वहां बड़े-बड़े मसले भी बहुत शांति और विनम्रता से हल हो जाते हैं।

ऐसी बात नहीं है कि वाद-विवाद, मतभेद हमेशा ही विध्वंसकारी या घातक होते हैं।विवेकपूर्ण बहसों, विमर्शों और विचारों के मंथन से ही आखिर में कुछ बेहतर निकल कर आता है। पर जब वाद-विवाद, स्वार्थ, गुस्से और अहंकार से दूषित हो जाए और हर व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो जाए, नए नजरिये का स्वागत न हो, तो वह सिर्फ कलह कहा जाएगा। वह घातक है। वहां सब

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

मौजूद है। साथ ही पूंजी की भारी कमी है, घरेलू कंपनियां घाटे में चल रही हैं, कर्ज में डूबी हैं और बैंकों की हालत भी ढीली है। अपेक्षित कर-संग्रह में सरकार विफल रही है जिसके कारण उसे बार-बार कर जमा करने और सख्तिडी छोड़ने की अपील करनी पड़ती है। सार्वजनिक कंपनियों की जमीन पर नजरें गड़ाए उद्योगपतियों को ध्यान में रख कर लाभ देने वाले उपक्रमों की भी बिक्री से पैसा उगाही कर सरकार वाहवाही को लूट सकती है लेकिन इससे आर्थिक संकट और बढ़ेगा ही। तात्कालिक कदम से ज्यादा भविष्य को ध्यान में रख कर

किसी भी मुद्दे या संघटन पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश
आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

बीमारियां खतरनाक स्तर तक बढ़ गई हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा में प्रदूषण और आर्द्रता बढ़ने से वातावरण में 2.5 पीएम के सूक्ष्म कण, ओजोन, नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। प्रदूषण और आर्द्रता से ग्राउंड लेवल पर ओजोन का स्तर बढ़ रहा है। इससे नाक और सांस की नलिकाओं में सूजन और संक्रमण की शिकायत बढ़ रही है जिससे लोग खांसते-खांसते परेशान हैं। प्रदूषण और आर्द्रता बढ़ने से फोटो केमिकल स्मॉग भी बन रहा है। प्रो जेवी सिंह के मुताबिक फोटो केमिकल स्मॉग में निचली स्तह पर ओजोन की मात्रा लगातार बढ़ रही है। यह ओजोन नाक और सांस की नलिकाओं के म्यूकस (द्रव्य पदार्थ) को नुकसान पहुंचा रही है। इससे आम लोगों में सांस की नलिकाओं में सूजन और संक्रमण हो रहा है। प्रदूषण से अस्थमा और क्रानिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) से पीड़ित मरीजों की सांस उखड़ने लगी है।

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जिस तरह विकराल रूप धारण कर रही है, उससे लगता है कि कुछ ही सालों में विकासशील देशों में रहने वाले लोगों की औसत उम्र में और भी कमी आएगी। आमतौर पर शहरों में रहने वालों की प्रदूषण की समस्या से दो-चार होना पड़ता है, लेकिन अब गांवों और छोटे कस्बों में भी प्रदूषण की समस्या से लोगों को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत के अनेक प्रदेशों के किसानों द्वारा पाराली जलाने से वायु प्रदूषण, डीजे के शोर से ध्वनि प्रदूषण और उड़ती धूल के कणों से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि गांवों में रहने वाले लोग उन बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं, जो आमतौर पर शहरों की मानी जाती थीं।

पाराली जलाने से हवा और सेहत तो चौपट हो ही रही है, जमीन की उर्वरा-शक्ति में जबदस्त कमी देखी जा रही है। सर्वेक्षण के मुताबिक भूमि में अस्सी फीसद तक सल्फर, नाइट्रोजन और बीस फीसद अन्य पोषक तत्त्वों की कमी आई है। इसके अलावा जमीन में मौजूद ‘मित्रकीट’ नष्ट हो रहे हैं। कीटों का प्रकोप गांवों में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और भूमि की जल धारण क्षमता में कमी आ रही है। इस पर गौर करने की जरूरत है। शहरों में घरों और कारखानों का कचरा और गांवों में पाराली दोनों पर्यावरण की बर्बाद कर रहे हैं। प्रकाश प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर काबू पाने के उपाय जरूरी हो गए हैं।

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

कुछ एकतरफा होता जाता है। जहां किसी भी बात के समर्थन या पुष्टि के लिए वास्तविक और तर्कसंगत तथ्यों का उपयोग नहीं होता, वहां अक्सर एक हंगामा और एक-दूसरे पर दोषारोपण होता रहता है। भूत और भविष्य को लेकर आपसी खींचतान, छीछालेदारी से निरर्थक क्लेश पैदा होने लगता है। ऐसे में अपनी ठीक बात रखना भी व्यर्थ हो जाता है। उस समय खुद को मौन रखना या सही समय का इंतजार करना ही हितकर हो सकता है।

अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर विवाद गलत शब्दों के चयन, बोलने के तरीके और हमारी भाव-भंगिमा से ही बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमारा सचेत रहना तो जरूरी है ही, सकारात्मक सोच, सही आचरण और अन्य की मन:स्थिति को समझने का प्रयास काफी हद तक परिस्थिति को बेहतर कर सकता है। हमारा परिपक्व और विनम्र व्यवहार ही हमें उस कठिन रास्ते से पार लग सकता है।

कहीं आग लगती है तो हम उस पर पानी डालते हैं और उससे खुद को बचाने का प्रयास भी करते हैं। यही रवैया हमें अपने जीवन में भी रखना शायद बहुत जरूरी है। हर मिजाज के लोग हमें हर रोज मिलते हैं। उनके स्वभाव को हमें अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ‘जैसे को तैसा’ व्यवहार के बजाय अपने सहज और विनम्र स्वभाव के साथ युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण व्यवहार शायद एक उचित पहल होगी।

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

कुछ एकतरफा होता जाता है। जहां किसी भी बात के समर्थन या पुष्टि के लिए वास्तविक और तर्कसंगत तथ्यों का उपयोग नहीं होता, वहां अक्सर एक हंगामा और एक-दूसरे पर दोषारोपण होता रहता है। भूत और भविष्य को लेकर आपसी खींचतान, छीछालेदारी से निरर्थक क्लेश पैदा होने लगता है। ऐसे में अपनी ठीक बात रखना भी व्यर्थ हो जाता है। उस समय खुद को मौन रखना या सही समय का इंतजार करना ही हितकर हो सकता है।

अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर विवाद गलत शब्दों के चयन, बोलने के तरीके और हमारी भाव-भंगिमा से ही बढ़ जाते हैं। ऐसे में हमारा सचेत रहना तो जरूरी है ही, सकारात्मक सोच, सही आचरण और अन्य की मन:स्थिति को समझने का प्रयास काफी हद तक परिस्थिति को बेहतर कर सकता है। हमारा परिपक्व और विनम्र व्यवहार ही हमें उस कठिन रास्ते से पार लग सकता है।

कहीं आग लगती है तो हम उस पर पानी डालते हैं और उससे खुद को बचाने का प्रयास भी करते हैं। यही रवैया हमें अपने जीवन में भी रखना शायद बहुत जरूरी है। हर मिजाज के लोग हमें हर रोज मिलते हैं। उनके स्वभाव को हमें अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ‘जैसे को तैसा’ व्यवहार के बजाय अपने सहज और विनम्र स्वभाव के साथ युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण व्यवहार शायद एक उचित पहल होगी।

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

अखिलेश आर्यदु का जन्म 24 नवंबर 1968 में उत्तर प्रदेश के गाँव मालवा, मैनपुरी जिले के अम्बरगढ़ में हुआ था। फ़ैमिली के अलावा अखिलेश का कोई भी बहिष्करण नहीं है।

अखिलेश आर्यदु का ज



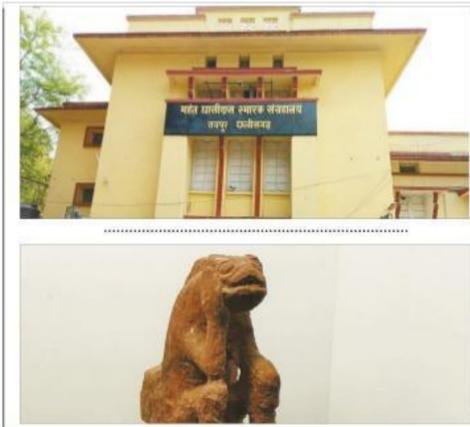
उत्तराखंड तीर्थ पुरोहित हकहकूकधारी महापंचायत के संयोजक सुरेश सेमवाल का कहना है कि हम तिरुपति मंदिर की तरह संपन्न नहीं हैं। सरकार ने गंगोत्री-युमनोत्री धाम के लिए आपदा के समय से लेकर अभी तक एक भी रुपए नहीं दिया है। हम जजमान और स्थानीय लोगों के सहयोग से काम करते हैं। चार धाम श्राइन बोर्ड बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने बिना पंडा समाज को विश्वास में लिए कर दिया हजारों परिवारों को बेघर करने की राज्य सरकार की नियत को सहन नहीं किया जाएगा।

बैरागी राजाओं के संग्रहालय में हैं बापू के तीन बंदर

अस्पतालों में मरीजों के अनुपात में नर्सों की कमी

राज सिंह

‘बुरा मत देखो’, ‘बुरा मत कहो’ और ‘बुरा मत सुनो’। नैतिक शिक्षा का उपदेश देती, बापू के इन तीन बंदरों की मूर्तियों को कौन नहीं जानता। बंदर की इन तीन मूर्तियों के माध्यम से महात्मा गांधी ने नैतिक शिक्षा का यह संदेश जन-जन तक पहुंचाया, लेकिन इन तीन बंदरों की मूर्तियों के इतिहास से आज भी अधिकतर लोग अनभिज्ञ हैं। मानव जाति को नैतिकता की सीख देती हुई, तीन बंदरों की पत्थर से बनी मूर्तियां रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं। संग्रहालय में लिखा हुआ है कि ये मूर्तियां 16 वीं या 70 वीं शताब्दी की हैं और इन्हें राजनंदगांव के पूर्व शासक महंत राजा घासीदास के व्यक्तिगत संग्रह से प्राप्त किया गया था। संभव है कि महात्मा गांधी ने भी यह संग्रहालय देखा हो और नैतिकता की शिक्षा देते हुए बंदरों की इन तीन मूर्तियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह संदेश जन-जन तक पहुंचा दिया। महंत घासीदास संग्रहालय छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में है। यह संग्रहालय राजभवन से मात्र कुछ ही कदम की दूरी पर है। इसे नंदगांव रियासत के बैरागी राजा महंत घासीदास ने सन 1875 में बनवाया था। नंदगांव रियासत की राजधानी राजनंदगांव में थी। 1953 में राजमाता जयंती देवी और उनके पुत्र राजा दिग्विजय दास ने इस गठन का पुनर्निर्माण कराया था। संग्रहालय के नए भवन का लोकार्पण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों किया गया। रानी जयंती देवी का विवाह 2 मार्च 1932 को नंदगांव के राजा सर्वेश्वर दास से कोलकता में हुआ था। राजकुमारी जयंती देवी मयूरभंज के राजा केशव चंद्र सेन की पौत्री थीं। राजा महंत घासीदास नंदगांव रियासत के आठवें राजा थे। 1 जनवरी 1948 को इस रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। उस वक्त रियासत के आखिरी राजा, दिग्विजय दास नाबालिग थे, इसलिए विलय की संधि पर राजमाता जयंती देवी ने हस्ताक्षर किए। महंत घासीदास



संग्रहालय एक पुरातात्विक संग्रहालय है जो भारत के अत्यंत प्राचीनतम 10 संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में बैरागी राजाओं के हथियारों के अतिरिक्त देवताओं की अनेक मूर्तियां, प्राचीन सिक्के और छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति से संबंधित अनेक चीजें प्रदर्शित की गई हैं। नंदगांव रियासत की स्थापना, वैष्णव परंपरा से संबंध रखने वाले निंबार्क संप्रदाय और निर्मोही अखाड़े के संत प्रसाद दास बैरागी ने की थी। प्रसाद दास बैरागी पंजाब से आए थे और वे बिलासपुर के निकट स्थित रतनपुर नामक स्थान पर मराठा राजा बिंबा जी के राजगुरु बन गए थे। प्रसाद दास बैरागी, सनातन धर्म की वैष्णव परंपरा का प्रचार करने के लिए पंजाब से 1665 में रतनपुर आए और



मराठा राजाओं ने उन्हें एक छोटी सी जमींदारी दान में दी। बाद में बैरागी संत के उत्तराधिकारी, महंत रघुवर दास और महंत हिमाचल दास ने तीन अन्य जमींदारी भी अपनी रियासत में शामिल कर ली। ये बैरागी राजा निर्मोही अखाड़े से संबंध रखते थे इसलिए उन्हें लड़ाई और शस्त्रों का भी अच्छा अनुभव था। राजनंदगांव के राजा सनातन धर्म के बहुत बड़े संतों में से थे। इसलिए वे राजा होने के साथ-साथ अन्य कई रियासतों के राजगुरु भी थे। उनकी संत प्रवृत्ति की झलक पत्थर से बनी इन तीन मूर्तियों में बड़ी आसानी से देखी जा सकती है जो कुछ भी न बोलकर, कई शताब्दियों से मानव जाति को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं।

(लेखक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी हैं)

राजीव जैन जयपुर।

राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के साथ नर्सों की भी भारी कमी से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में कुछ वर्षों में नर्सों की नियमित भर्तियां नहीं होने से ज्यादातर अस्पतालों में उनकी कमी हो गई है। प्रदेश के बड़े अस्पतालों में नियमित नर्सों के बजाए संचिदा पर नर्सिंगकर्मी लगाए गए हैं, जिनके भरोसे ही मरीजों की देखभाल हो रही है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में ही तय हिसाब से आधे से भी कम नर्सिंगकर्मियों के भरोसे मरीजों का इलाज हो रहा है। प्रदेश में एक तरफ जहां नर्सों की कमी है वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में युवा नर्सिंग की पढ़ाई करके भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जल्द ही प्रदेश में 15 हजार से ज्यादा नर्सों की भर्ती की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में नर्सों की कई श्रेणियों में बांट कर भर्तियां की जाती हैं। प्रदेश में एएनएम, एलएचवी, नर्स ग्रेड प्रथम और नर्स ग्रेड द्वितीय श्रेणी के पदों पर नर्सों की तैनाती उनके कोर्स के हिसाब से सरकारी अस्पतालों में होती है। एएनएम की नियुक्तियां ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होती हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। सरकार इन्हें भी संचिदा अर्थात् अनुबंध के आधार पर ही तैनात करने पर ज्यादा जोर देती है। चिकित्सा जैसे पवित्र काम के लिए अनुबंध पर नर्सों को लगाने से उनके काम में गुणवत्ता के साथ ही मरीजों की देखभाल जैसे मानवीय पहलू गायब ही रहते हैं। नर्सिंगकर्मियों की कमी पर कई बार डॉक्टरों ने सरकार के आला अफसरों का ध्यान भी दिलाया। इसके बावजूद कार्डिनल के मानकों की राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयपुर के सवाई मानसिंह में तो हालत बदतर ही है। इस अस्पताल में मरीजों की संख्या के हिसाब से करीब चार हजार नर्सिंगकर्मी होने चाहिए जबकि मौजूदा समय में सिर्फ 1500 ही नर्सिंगकर्मी कार्यरत हैं। यह अस्पताल मरीजों की संख्या के हिसाब से हर साल एम्स दिल्ली का भी रेकर्ड तोड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में मौजूदा में करीब 64 हजार नर्सिंगकर्मी कार्यरत हैं, इनमें से पंद्रह हजार तो अनुबंध पर ही हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 20 हजार नए नर्सिंगकर्मियों की तुरंत जरूरत है। वहीं बेरोजगार नर्सिंग छात्र भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।



स्वास्थ्य विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। प्रदेश में जल्द ही 737 डॉक्टर और 15500 नर्सिंगकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट प्रावधान भी कर दिया है। नई भर्तियों के बाद अस्पतालों में नर्सों की कमी दूर हो जाएगी। नई भर्तियों के बाद अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार के लिए भी सरकार जरूरी कदम उठाएगी। नर्सों की कमी से होने वाली परेशानियों से सरकार चिंतित है। - रघु शर्मा, चिकित्सा मंत्री

राजस्थान

श्राइन बोर्ड के खिलाफ सड़कों पर उतरे पंडे-पुरोहित

सुनील दत्त पांडेय देहरादून।

उत्तराखंड के चारों धामों और 51 मंदिरों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड श्राइन बोर्ड के गठन के निर्णय के खिलाफ यहां के पंडे-पुरोहित सड़कों पर उतर आए हैं। पंडे-पुरोहितों ने ऐलान किया है कि वे राज्य सरकार के खिलाफ तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक राज्य सरकार उत्तराखंड श्राइन बोर्ड बनाने का फैसला वापस नहीं लेती। पुरोहितों ने इसे सरकार का काला कानून बताया है। इसके खिलाफ देहरादून, हरिद्वार, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ समेत उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला फूंकना। पुरोहितों का कहना है कि ऐसा करके राज्य सरकार हमारे हक हकूक पर डाका डालना चाहती है। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के दौरान पंडे-पुरोहितों ने विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया और सरकार पर पंडे-पुरोहितों के आर्थिक हितों पर हमला करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल का कहना है कि प्रदेश सरकार हजारों सालों से उत्तराखंड के मंदिरों और चारों धामों में चल रही प्राचीन वैदिक सभ्यता को मिटाने पर तुली है। इस समय उत्तराखंड के चार धामों और चिन्हित किए गए 51 मंदिरों में स्थानीय पांडे और पुजारियों का आधिपत्य है। वहीं उत्तराखंड के चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़ीनाथ और केदारनाथ के लिए राज्य सरकार ने बड़ी केदार मंदिर समिति का गठन किया है। इन चारों धामों की व्यवस्था फिलहाल मंदिर समिति देखती है, जिसके अध्यक्ष महामंत्री और अन्य पदाधिकारियों तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार ही करती है। उत्तराखंड भाजपा के कई विधायक भी सरकार



उत्तराखंड चारधाम श्राइन बोर्ड का गठन प्रदेश में बड़ी तादाद में आ रहे तीर्थयात्रियों की सुख-सुविधाओं के लिए किया गया है। अनुमान है कि 2030 तक चार धामों में एक करोड़ तीर्थयात्री हर साल आया करेंगे, यह संख्या बढ़ भी सकती है। इसलिए श्राइन बोर्ड का गठन जरूरी है। पंडे पुरोहितों के हितों का भी श्राइन बोर्ड में पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बारे में विपक्ष गलत राजनीति कर रहा है और गलत परंपराओं को जन्म दे रहा है। -त्रिवेन्द्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री

महापंचायत ने आगे की रणनीति तय करने के लिए कोर कमेटी के गठन का फैसला किया है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार को इस निर्णय को काला कानून करार दिया है। -हरीश डिमरी, उत्तराखंड पंडे पुरोहित महापंचायत के महामंत्री वधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक

उत्तराखंड

उत्तराखंड श्राइन बोर्ड के गठन का फैसला पुरोहितों को बिना विश्वास में लिए किया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सालों से मंदिरों और चार धामों की जो व्यवस्था चली आ रही थी। वह वैदिक कालीन परंपरा है, जिसे राज्य सरकार ध्वस्त करना चाहती है। कांग्रेस इस मामले को विधानसभा में जोर-शोर से उठाएगी। -डॉ. इंदिरा हृदयेश, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता



राज्य सरकार ने चार धाम श्राइन बोर्ड का गठन करने का फैसला लेते वक्त पर्वतीय क्षेत्र के भाजपा विधायकों को विश्वास नहीं लिया, जिससे हमारे लिए असहज स्थिति बनी हुई है और तीर्थ पुरोहित इस बोर्ड के गठन का जोरदार विरोध कर रहे हैं। -केदार सिंह रावत, गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक

के इस फैसले से सहमत नहीं हैं और वे राज्य में पंडित-पुरोहितों के आंदोलित होने से परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का भय है। कांग्रेस ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देकर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उत्तराखंड के पंडे पुरोहितों के साथ उत्तराखंड के विभिन्न ब्राह्मणों के संगठन भी जुड़ गए हैं।

हरिद्वार की हरकी पैड़ी की प्रबंध कारिणी संस्था श्री गंगा सभा, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा जैसे तमाम संगठन भी पुरोहितों के साथ खड़े हैं। साथ ही चार धाम पुरोहित समाज को परिषद का पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। उत्तराखंड पंडे-पुरोहित महापंचायत के महामंत्री हरीश डिमरी की कहना है कि महापंचायत ने आगे की रणनीति तय करने के लिए

कोर कमेटी के गठन का फैसला किया है। विधानसभा कूच का फैसला अपनी जगह कायम है। चार धाम श्राइन बोर्ड बनाने के सरकार के फैसले को लेकर विवाद शुरू हो गया है। चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस निर्णय को काला कानून करार दिया है।

वित्तीय संकट के बीच शताब्दी समारोह

गजेंद्र सिंह नई दिल्ली।

अपनी स्थापना के सौ साल की दौड़ पूरी करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय दसवां विश्वविद्यालय बन गया है। तमाम झंझावात को पार करते हुए विश्वविद्यालय इस पड़ाव पर खड़ा है कि वह शताब्दी समारोह का जश्न भी वित्तीय संकट के बीच मना रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से सौ साल पूरा करने वाले विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान राशि भी बंद हो चुकी है और लखनऊ विश्वविद्यालय को अपनी विरासत संभालने को यह मदद भी नहीं मिल पाएगी। वित्तीय संकट से जुड़ा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान भी 1994 से बंद है।



लखनऊ विश्वविद्यालय अपने कुल बजट का करीब 150 करोड़ रुपए वेतन पर खर्च करता है। राज्य सरकार की ओर से विश्वविद्यालय को तीन करोड़ रुपए ही दिए जाते हैं। सरकार के पास विश्वविद्यालय के वेतन हिस्से का करीब 160 करोड़ रुपए आता है लेकिन अनुदान बंद किए जाने की वजह से यह भार विश्वविद्यालय प्रशासन को खुद वहन करना पड़ता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. एसपी सिंह बताते हैं कि 1994 में तमाम अनियमितताओं के बाद सरकार ने विवि का अनुदान फ्रीज (रोक) कर दिया। विश्वविद्यालय में कई सालों से पदों के लिए विज्ञापन नहीं निकले लेकिन भर्तियां होती गईं। कई प्राध्यापक भी इसी के तहत भर्ती हुए जो अच्छी तनखावा पाते हैं। विश्वविद्यालय

ये विवि हुए सौ साल के

वर्ष	विश्वविद्यालय
1857	कोलकाता, मद्रास, बांबे विश्वविद्यालय
1887	इलाहाबाद विश्वविद्यालय
1916	काशी हिंदू विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय
1917	पटना विश्वविद्यालय
1918	हैदराबाद विश्वविद्यालय
1920	अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय

खुद से 120 करोड़ रुपए कमाता है जबकि उसका वेतन पर खर्च 150 करोड़ रुपए से अधिक होता है। ऐसे में विश्वविद्यालय अपने कई कार्यों को करने में असमर्थ है। डॉ. एसपी सिंह बताते हैं कि यूजीसी की ओर से सौ साल पूरे करने वाले विश्वविद्यालयों को अच्छी खासी धनराशि दी जाती थी, लेकिन पिछली पंचवर्षीय योजना के तहत यह बंद

कर दिया गया और फंड करने का प्रारूप बदल दिया गया। डॉ. एसपी सिंह कहते हैं कि अगर यूजीसी की ओर से यह धनराशि मिलती तो विश्वविद्यालय अपनी हालत को सुधार सकता था। क्योंकि 165 साल हो गए इस भवन को जिसके जीर्णोद्धार के लिए काफी रुपए लगेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष नीरज जैन कहते हैं कि विश्वविद्यालय के सौ वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार से मांग है कि इसे विशेष दर्जा दिया जाए जिससे इसकी अहमियत बनी रहे। यूजीसी से जुड़े एक अधिकारी बताते हैं कि सौ साल पूरे होने पर जो दस करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाती थी उसे 12वीं योजना के तहत बंद कर दिया गया है। यह 2012 से 2017 तक चलाई गई थी।

गौरवशाली है इतिहास

एक मई, 1864 को हुसैनबाद कोठी में शुरू हुए एक कॉलेज को अंग्रेज गवर्नर की याद में बने कैनिंग कॉलेज को 1920 में विश्वविद्यालय का रूप दिया गया और 1921 में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। 178 कॉलेजों के साथ एक लाख 60 हजार विद्यार्थियों वाले इस विश्वविद्यालय की काफी रकम वेतन के बाद परीक्षा आयोजित करने में खर्च

होती है। विश्वविद्यालय के साथ काफी पुराना 1870 का आइटी महिला कॉलेज भी जुड़ा हुआ है। इससे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी जुड़ा था, जिसे 2000 के बाद अलग विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना आवासीय विवि के रूप में हुई थी जबकि अन्य की सिर्फ संबद्धता के लिए की गई थी। इलाहाबाद विवि को 1887 में स्थापना के 33 साल बाद 1920 में आवासीय विवि स्थापित किया गया।

याद रहेगा विश्वविद्यालय का अतीत

1928 में पंडित नेहरू को बचाने के लिए यहां के छात्रों ने लाठियां खाई थीं। 1929 में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू का भाषण हो चुका है। जेपी आंदोलन का भी गवाह रहा है यह विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय से निकले शंकर दयाल शर्मा ने देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। राजनेता हरीश रावत, केसी पंत, सुरजीत सिंह बरनाला, विजयराजे सिंधिया, राम गोविंद चौधरी, दिनेश शर्मा, इसरो की ऋतु करिधल, गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, क्रिकेटर सुरेश रैना और कई जाने-माने पत्रकार यहां से पढ़े हुए हैं।

